IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आत्मनिर्भर भारत में भूमिका का अध्ययन''

डॉ0 मनीषा सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
रजत कॉलेज लखनऊ (उ0प्र0)

सारांश :— शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति का सामाजिक विकास करना है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और उसकी योग्यताओं को इस प्रकार विकसित करती है, जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यकम मे विद्यार्थियों को आत्मनिीर भी होना आवाश्यक है। जिससे उनक तार्किक एवं सीखने की गति में वृद्धि कि जा सक। अतः माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का शिक्षा क द्वारा विकास के लिये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क प्रयोगों की मदद से विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का विकल्प भी छात्रों को दिया जाएगा। छठी के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का उद्देश्य पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है ताकि छात्रों के पास शैक्षिक पाठ्यक्रमों का चयन करने का विकल्प हो और वे अपनी योग्यता व रुचियों के अनुसार जीवन में अपने लिए आगे का रास्ता स्वयं चुन सकते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द – माध्यमिक स्तर, आत्मनिर्भर भारत

प्रस्तावना

आज हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गये हैं। लाखों लोगों ने अपने को इसी आजादी के लिए बलिदान किया था, परिवार छोड़े थे, अपनों को खोया था, अपने जमे–जमाये कारोबार की शहादत दे दी थी, बड़े–बड़े पदों को लात मारी थी और राष्ट–देवता की बलिवेदी पर कुर्बान हो गये थे। इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी जब हम हिन्दुस्तान के स्कूलों से हिन्दी को गायब पाते हैं, संस्कृत की भारी उपेक्षा देखते हैं, किसानों को सभी ओर से कमजोर पाते हैं, गायों को मरता हुआ पाते हैं, वाणी और लेखनी को परावलम्बन की त्रासदी से जकड़ा पाते हैं, अनेक देशवासियों को आर्थिक दासता से ग्रसित देखते हैं तथा नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों की गिरावट के दर्शन स्थान–स्थान पर होते हैंय तब लगता है कि भारत में एक सांस्कृतिक क्रान्ति की और आवश्यकता है। मैं तो कहूँगी कि इस राष्ट्र को नेताओं के साथ–साथ सृजेताओं की अधिक आवश्यकता है। इसके लिए धर्मतन्त्र व राजतन्त्र का सहगमन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना एक आदर्शवादी राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। जीवन तो सभी जीते हैं लेकिन पेट–प्रजनन से ऊपर उठकर संस्कृति, समाज और राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ जाने वाले लोग अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराकर अमर हो जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों के सफल कार्यकाल में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊँचाइयां और उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं 'आत्म निर्भर भारत' प्रधानमंत्री के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करता है। नई शिक्षा नीति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ–साथ, भारतीय परम्पराओ, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, पुनर्स्थापन एवं प्रसार पर जोर देती हैं, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके अंतर्गत सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा।प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की बात कही है जो समयानुकूल और उचित निर्णय हैं। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक की शिक्षा अब 5+3+3+4 पर आधारित होगो जो 3 से 18 वर्ष के बच्चो के लिए निर्धारित किया गया है। 2025 तक शिक्षा के सार्वभौमिकिकरण की बात की गई हैं। छात्रों पर किसी भी एक भाषा को थोपने के बजाय इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया हैं। साथ ही बहुभाषा का विकल्प भी बच्चो को प्रदान किया गया है जिससे उनका मानसिक विकास और अच्छे से हो सके।

मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए सुगम शिक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके लिए नामांकन को सत प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है. जाहिर सी बात है कि एक अच्छा अध्यापक ही एक बेहतर विद्यार्थी तैयार कर सकता है. इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा से सम्बन्धी कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। इसके अंतर्गत जहाँ माध्यमिक शिक्षा तक का विनिमयन का अधिकार राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्राक्षिण परिषद् को दिया गया है तो वही उच्च शिक्षा के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा अनुदान परिषद् की स्थापना करने की बात की गई है। इसके अंतर्गत, विधि और स्वास्थ्य को छोड़कर, विभिन्न शाखाओ का सृजन किया जायेगा जो वर्तमान में कार्यरत संगठनों का विघटन करके बनाया जाएगा। यही संगठन विनिमयन से लेकर अनुदान तक के सारे कार्य देखेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान बनाने की बात की गई जो शोध को बढ़ावा देगा जिससे देश विश्व के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ सके तथा अतीत की गरिमा पुनः स्थापित की जा सके।

साक्षरता की दिशा में बढ़ते कदम :–

वर्ष 1951 में देश में साक्षरता दर लगभग 18 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में 73 प्रतिशत तक पहुँची तथा 2021 में साक्षरता दर 74 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार का ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर है। केन्द्र सरकार ने देश में 15 हजार से अधिक माध्यमिक स्तर के आदर्श स्कूल बनाने का निर्णय लिया है।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना :–

आत्मनिर्भर भारत एक वाक्यांश है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने देश की आर्थिक विकास योजनाओं के संबंध में उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया। यह वाक्यांश मोदी सरकार की विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने और इसे और अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं के लिए एक अध्यर्थक अवधारणा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रथम लोकप्रिय उपयोग 2020 में भारत के कोविड–19–महामारी से सम्बन्धित आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान हुआ था। तब से, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है। और प्रेस विज्ञप्तियों, बयानों और नीतियों में रक्षा मंत्रालय। सरकार ने भारत की नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत के 2021 के केन्द्रीय बजट के सम्बन्ध में भी इस वाक्यांश का उपयोग किया है।

आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अपनी पूरी क्षमता से नवोन्मेषी प्रयोग और वैचारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तकनीकी ज्ञान और कौशल संवर्धन से विद्यार्थियों में उद्यमी दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है और उन्हें स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग सुनिश्चित करना भी शिक्षण संस्थाओं का दायित्व है।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास :–

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना ह, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके, जो राष्ट्र भक्ति से ओत–प्रोत हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो और जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। विद्या भारती के मार्गदर्शन में देश भर में 13,000 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 40 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। विद्या भारती, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र भक्ति से ओत–प्रोत युवा पीढ़ी के निर्माण में संलग्न है।

नई शिक्षा नीति से समर्थ भारत का सपना :

नई शिक्षा नीति बाल अवस्था से ही नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके साथ ही देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत करती है। इसमें पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की

बात कही गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालपन से ही भारतीयता के मूल स्वभाव के अनुरूप विद्यार्थी का आचरण और व्यवहार की शिक्षा देना है जिससे उनमें ज्ञान के साथ सामाजिकता का यथोचित विकास होने की संभावनाएं बलवती हो। देश में सौ फीसदी उच्च शिक्षित समाज के लक्ष्य पर काम करने के लिए इस बात की जरूरत है कि स्कूल से ड्रॉप आउट को खत्म किया जाये। नई शिक्षा नीति में 2030 तक माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवोन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। संख्यात्मक दृष्टि से बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा,इसमें 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने की व्यापक योजना है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं,पाठ्येतरगतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किए जाने पर जोर दिया गया है,जिससे विद्यार्थी ज्ञान के साथ कौशल विकास की ओर प्रवृत हो सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 दिसम्बर 2021 को 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन एवं टेबलेट वितरण का उद्घाटन कर युवा पीढ़ी में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित किया है।

आत्मनिर्भर बनाने में सहायक नई शिक्षा नीति :2020

आधुनिक समाज साक्षरता, शिक्षा और अनुसंधान का परिणाम है। आज हमारी जो भी तरक्की हुई है वह शिक्षा का ही परिणाम है। माचिस की तीली से लेकर स्मार्टफोन तक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान का ही नतीजा है। लेकिन जैसे–जैसे समाज ने डिजिटलाइजेशन के आगमन के साथ प्रगति की है, आम जनता की शिक्षा की जरूरतें भी बदल गई हैं। समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर कुछ दशक के बाद एक नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति तैयार की जाती रही है ताकि उन बदली हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब तक भारत ने इस तरह के तीन सुधार देखे हैं, पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा हाल ही में इसे अंजाम दिया गया है।

ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति देखा जाए तो समग्र शिक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति शिक्षा के सार्वभौमिकरण और व्यावसायिक अध्ययन के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जहां पहले शिक्षा का फोकस लोगों को साक्षर बनाना और उन्हें सुरक्षित नौकरियां दिलाने में मदद करना था, वहीं नई नीति गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है। समावेशी और निष्पक्ष शिक्षा के रूप में सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ी कुंजी है। समावेशी और निष्पक्ष शिक्षा एक समावेशी समुदाय को गढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सपने देखने, उसे साकार करने और देश के विकास में अपना योगदान देने का अधिकार है। मानकीकृत और सार्वभौमिक साधनों को सुनिश्चित करने के संदर्भ में एक व्यापक शोध किया गया जिससे प्राप्त आंकड़ों से यह पता चला कि देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में सामाजिक और आद्दथक रूप से वंचित समूहों का अनुपात काफी बड़ा है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक इलाकों की पहचान उन आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी बच्चे को जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इस नीति में यह प्रस्तावित किया गया है कि उन क्षत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। ये क्षेत्र समग्र रूप से भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अधिक सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्र एक साथ आगे बढ़ता रहे और प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त बने, सरकार ने यह तय किया है कि उच्च शिक्षा के लिए भी समानता का समावेश हो। एक प्रतिष्ठित संस्थान से हासिल की गई शिक्षा से लोगों को ऐसे कई अवसर मिल सकते हैं जो समाज के सभी वर्गो के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नई शिक्षा नीति विशेष शिक्षा क्षेत्र पर खास जोर देने के साथ सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। इस नीति ने उच्च शिक्षण संस्थानों से फीस कम करने और यहां तक कि सामाजिक रूप पिछड़े व आद्दथक दृष्टिकोण से कमजोर तबके के छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि प्रत्येक

छात्र को अवसर मिल सके। कौशल आधारित नजरिये से देखा जाए तो नई शिक्षा नीति एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने में सक्षम है जो विशेषज्ञता और कौशल से बेहतर रूप से सुसज्जित होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अपनी विनिर्माण इकाइयों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश की जनता के पास सामयिक कौशल हो। विनिर्माण इकाइयों की मजबूती के लिहाज से तो यह देश को सक्षम बनाता ही है, इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा भी बढ़ेगा और साथ ही मेक इन इंडिया अभियान को भी यह आगे बढ़ाएगा।

उपसंहार :–

देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समावेशी विकास की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता के अनुसार प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक साल 2022 तक विकसित किया जाएगा। प्रत्येक माता–पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिले और नई शिक्षा नीति इसका मार्ग प्रशस्त करती है। माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्ष 2035 तक 50 फीसदी तक पंजीयन का लक्ष्य है जबकि फिलहाल यह महज 26.3 प्रतिशत ही है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा में इसे व्यापक,रचनात्मक और बहुआयामी बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अलग से कोचिंग की सरकार के द्वारा की गयी है।

सन्दर्भ :–

- बढेगा शिक्षा का दायरा, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी : दैनिक जागरण समाचार पत्र,कानपुर संस्करण, 2 फरवरी 2022
- तकनीकी की उडान : अमर उजाला समाचार पत्र मं प्रकाशित.
- साक्षरता की दिशा में बढ़ते कदम : दैनिक जागरण समाचार पत्र,कानपुर संस्करण, 2 फरवरी 2022.
- संजय पोखरीयाल : दैनिक जागरण समाचार पत्र, https:// www. jagran. com/ editorial / apnibaat-new-education-policy-helps-in-making-self-reliant-jagran-special-20634619.html
- Mission Global Standing (Achieve global standards; **Samarth Bharat Sashakt Bharat** – Powerful Capable India; Contributions to the strategic sector).
- *https://www.venturecenter.co.in ›*